



214hi04

4

मॉड्यूल - 2

अर्थव्यवस्था के विषय में



टिप्पणी

## अर्थव्यवस्था - अभिप्राय तथा प्रकार

प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज के पास उपलब्ध तथा ज्ञात दुर्लभ संसाधनों को प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करना है। इन आवश्यकताओं की तुष्टि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन तथा उपभोग द्वारा की जा सकती है। उत्पादन के लिये, उत्पादन के साधन कुछ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन आर्थिक गतिविधियों से आर्थिक इकाइयों को आय प्राप्त होती है, जिसे या तो उपभोग कर लिया जाता है अथवा बचत कर लिया जाता है अथवा निवेश कर दिया जाता है। इन लाभदायक गतिविधियों तथा संचित कमाई के कारण कुछ देशों में तीव्र गति से संवृद्धि होती है, जबकि अन्य इतनी उच्च संवृद्धि की दर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप कुछ अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति प्राप्त कर लेती हैं जबकि अन्य अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं रह जाती हैं। इन्हें धनी तथा निर्धन अर्थव्यवस्थाएं भी कहा जाता है। हम अर्थव्यवस्थाओं को संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर भी देख सकते हैं। उपलब्ध संसाधन निजी स्वामित्व अथवा सामूहिक स्वामित्व में हो सकते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास के स्तर पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। इस पाठ में हम इन सभी पदों की सरल प्रकार से व्याख्या करेंगे ताकि आप एक अर्थव्यवस्था के अर्थ और प्रकृति को समझ सकें तथा भेद कर सकें और इनके विभिन्न प्रकारों को समझ सकें।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य होंगे कि :

- अर्थव्यवस्था के अर्थ की व्याख्या कर सकें;
- विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठनों में स्वामित्व तथा संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर तथा विकास के स्तर के आधार पर भी अन्तर कर सकें;
- आर्थिक विकास तथा आर्थिक संवृद्धि का अर्थ समझ सकें;
- आर्थिक विकास तथा आर्थिक संवृद्धि में भेद कर सकें;
- आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारकों को समझ सकें।



## 4.1 अर्थव्यवस्था का अर्थ

अर्थव्यवस्था मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिये एक मानव निर्मित संगठन है। ए.जे. ब्राउन के अनुसार, “अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं।” जिस विधि से मनुष्य जीविका प्राप्त करने का प्रयास करता है वह समय तथा स्थान के सम्बन्ध में भिन्न होती है। प्राचीनकाल में, ‘जीविका प्राप्त करना’ सरल था परन्तु सभ्यता के विकास के साथ यह अत्यंत जटिल हो गया है। यहां यह ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिस विधि से व्यक्ति जीविका अर्जन करता है वह वैध तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अन्यायपूर्ण तथा अवैध कार्य जैसे लूटपाट, तस्करी से भी किसी को आय अर्जित हो सकती है परन्तु इसे लाभदायक आर्थिक गतिविधि अथवा जीविका प्राप्त करने की पद्धति की श्रेणी में नहीं लेना चाहिये। इसलिये यह कहना उपयुक्त होगा कि अर्थव्यवस्था एक संरचना है जहां सारी आर्थिक गतिविधियां पूरी होती हैं।

### अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. आर्थिक संस्थाएं मानव निर्मित होती हैं। अतः अर्थव्यवस्था वैसी ही होती है, जैसी हम उसे बनाते हैं।
2. आर्थिक संस्थाएं सृजित, विघटित, प्रतिस्थापित अथवा परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिये यू.एस.एस.आर. में 1917 में साम्यवाद ने पूंजीवाद को विस्थापित कर दिया तथा 1989 में भूतपूर्व यू.एस.एस.आर. में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला के माध्यम से साम्यवाद ध्वस्त हो गया। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों द्वारा हमने जर्मांदारी पद्धति का उन्मूलन कर दिया तथा अनेक भूमि सुधार लागू किये।
3. आर्थिक गतिविधियों के स्तर में परिवर्तन होता रहता है।
4. उत्पादक तथा उपभोक्ता समान व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार उनकी भूमिका दोहरी होती है। उत्पादकों के रूप में वे कार्य करते हैं तथा कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसी को उपभोक्ताओं के रूप में उपभोग करते हैं।
5. उत्पादन, उपभोग तथा निवेश अर्थव्यवस्था की अति आवश्यक गतिविधियां होती हैं।
6. आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्थाओं में हम मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं।
7. आजकल अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को अवांछनीय समझा जाता है तथा सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों एवं बाजार शक्तियों की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की वरीयता में वृद्धि हो रही है।

## 4.2 अर्थव्यवस्था के प्रकार

जैसा कि आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था एक मानव-निर्मित संगठन है, जिसका समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सृजन, विघटन तथा उसमें परिवर्तन किया जाता है। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक पद्धतियों में निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर भेद कर सकते हैं।



टिप्पणी

#### 4.2.1 उत्पादन के साधनों अथवा संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर

संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का पूर्ण स्वामित्व हो सकता है। उन्हें इनका प्रयोग कर मन चाहा लाभ कमाने की छूट हो सकती है। अथवा ये सामूहिक स्वामित्व (सरकारी नियंत्रण) में हो सकते हैं तथा सम्पूर्ण समाज के सामूहिक कल्याण के लिये इनका उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्तर तथा लाभ के उद्देश्य की कसौटी के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का नामकरण इस प्रकार हो सकता है:

- (अ) पूँजीवादी अथवा स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था
- (ब) समाजवादी अथवा केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था
- (स) मिश्रित अर्थव्यवस्था

अब हम इनकी मुख्य विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे।

##### (अ) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था

पूँजीवादी या स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं का प्राचीनतम स्वरूप है। प्राचीन अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों में ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ के पक्षधर थे। वे आर्थिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम स्तर तक सीमित रखना चाहते थे। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं;

###### (i) निजी संपत्ति

पूँजीवादी प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी होने का अधिकार होता है। व्यक्ति अपनी संपत्ति को पाकर उसे अपने परिवार के लाभार्थ प्रयोग करने को स्वतंत्र होते हैं। भूमि, मशीनों, खानों, कारखानों के स्वामित्व, लाभ कमाने और धन संग्रह करने पर कोई रुकावट नहीं लगाई जाती है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम अन्तरित हो जाती है। इस प्रकार उत्तराधिकार का नियम निजी संपत्ति व्यवस्था को जीवित रखता है।

###### (ii) उद्यम की स्वतंत्रता

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार नागरिकों की उत्पादक गतिविधियों में समन्वय लाने का प्रयास नहीं करती। सभी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनने को स्वतंत्र होते हैं। उद्यम की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी फर्में संसाधन प्राप्त कर उन्हें अपनी किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन में लगाने के लिये स्वतंत्र होती हैं। ये फर्में अपने इच्छित बाजारों में अपना उत्पादन बेचने को भी स्वतंत्र होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक श्रमिक अपना रोजगार और रोजगारदाता चुनने को स्वतंत्र रहता है। छोटी व्यवसायिक इकाइयों में उनके मालिक स्वयं ही उत्पादन से जुड़े जोखिम उठाते हैं तथा लाभ अथवा हानि उठाते हैं। किन्तु आधुनिक निगमित व्यवसाय में जोखिम अंशधारियों के हिस्से में आते हैं और व्यवसाय का संचालन वेतनभोगी ‘निदेशक’ करते हैं। अतः लाभ कमाने के लिये अपनी पूँजी को प्रयोग कर अपना ही नियंत्रण होना आवश्यक नहीं रह गया है। सरकार या कोई अन्य संस्था श्रमिकों के किसी उद्योग में आने या उससे बाहर जाने पर कोई बंधन नहीं लगती। प्रत्येक श्रमिक वही रोजगार चुनता है जहां से उसे अधिकतम आय प्राप्त हो सके।



### (iii) उपभोक्ता प्रभुत्व

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता राजा के समान होता है। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टिदायक वस्तुओं और सेवाओं पर अपनी आय खर्च करने को पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में उत्पादन कार्य उपभोक्ताओं द्वारा किये गये चयनों के अनुसार किये जाते हैं। उपभोक्ता की निर्बाध स्वतंत्रता को ही उपभोक्ता की सत्ता का नाम दिया जाता है।

### (iv) लाभ का उद्देश्य

पूंजीवाद में मार्गदर्शन करने का सिद्धान्त स्वयं का हित होता है। उद्यमी जानते हैं कि अन्य उत्पादक साधनों को भुगतान के बाद लाभ अथवा हानि उनकी होगी। अतः वे सदैव लागत को न्यूनतम और आगम को अधिकतम करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि उनको मिलने वाला अन्तर (लाभ) अधिकतम हो जाए। इसी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कुशल और स्वयं निर्यात्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है।

### (v) प्रतियोगिता

पूंजीवादी पद्धति में किसी व्यवसाय में फर्मों के प्रवेश और उसकी निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु और सेवा के बहुत से उत्पादक बाजार में वस्तु की आपूर्ति कर रहे होते हैं। इस कारण कोई फर्म सामान्य से अधिक लाभ नहीं कमा पाती। प्रतियोगिता पूंजीवाद की एक आधारभूत विशेषता है और इसी के कारण उपभोक्ता का शोषण से बचाव होता है। यद्यपि आजकल फर्मों के बड़े आकार और उत्पाद विभेदन के कारण बाजार में कुछ एकाधिकारी प्रवृत्तियां पनप रही हैं, फिर भी फर्मों की बड़ी संख्या और उनके बीच कड़ी प्रतियोगिता साफ दिखाई पड़ जाती है।

### (vi) बाजारों और कीमतों का महत्व

पूंजीवाद की निजी संपत्ति, चयन की स्वतंत्रता, लाभ का उद्देश्य और प्रतियोगिता की विशेषताएं ही बाजार की कीमत प्रणाली के सुचारू रूप से काम करने के लिये उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। पूंजीवाद मूलतः बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक वस्तु की एक कीमत होती है। उद्योगों में मांग और आपूर्ति की शक्तियां ही कीमत का निर्धारण करती हैं। जो फर्म उस निश्चित कीमत के अनुसार अपने उत्पादन को ढाल पाती हैं वही समान्य लाभ कमाने में सफल रहती हैं। अन्यों को उद्योग से पलायन करना पड़ता है। प्रत्येक उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनसे उसे अधिकतम लाभ मिल सके।

### (vii) सरकारी हस्तक्षेप का अभाव

स्वतंत्र बाजार अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समन्वयकारी संस्था का कार्य कीमत प्रणाली करती है। सरकारी हस्तक्षेप और सहारे की कोई आवश्यकता नहीं होती। सरकार की भूमिका बाजार व्यवस्था के स्वतंत्र और कुशल संचालन में सहायता करती है।



टिप्पणी

## आज के विश्व में पूंजीवाद

आजकल विश्व में शुद्ध रूप से पूंजीवाद देखने को नहीं मिलता है। यू.एस.ए. (USA), यू.के. (UK), फ्रांस, नीदरलैण्ड, स्पेन, पुर्तगाल, आस्ट्रेलिया आदि की अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक विकास में उनकी अपनी सरकारों की सक्रिय भूमिका सहित पूंजीवादी देशों के रूप में जाना जाता है।

### (ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था

समाजवादी या केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में समाज के सभी उत्पादक संसाधनों पर समाज के बेहतर हितों की पूर्ति के लिये सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। सारे निर्णय किसी केन्द्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा लिये जाते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

#### (i) उत्पादन के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व

समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता की ओर से उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यहां निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी उत्पादक इकाई का स्वामी नहीं हो सकता। वह धन संग्रह कर उसे अपने उत्तराधिकारियों को भी नहीं सौंप सकता। परन्तु लोगों को व्यक्तिगत प्रयोग के लिये कुछ दीर्घोपयोगी उपभोक्ता पदार्थ अपने पास रखने की छूट होती है।

#### (ii) समाज के कल्याण का ध्येय

सरकार, समष्टि स्तर पर, सभी निर्णय निजी लाभ नहीं बल्कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है। मांग और आपूर्ति की शक्तियों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। सभी निर्णय ध्यानपूर्वक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होकर लिये जाते हैं।

#### (iii) केन्द्रीय नियोजन

आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक मूलभूत विशेषता है। केन्द्रीय योजना प्राधिकरण संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कर उन्हें राष्ट्रीय वरीयताओं के अनुसार आबंटित करता है। सरकार ही वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'उत्पादन, उपभोग और निवेश संबंधी सभी आर्थिक निर्णय लेती है। योजना अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और संसाधनों का कुशल प्रयोग सुनिश्चित करते हैं।

#### (iv) विषमताओं में कमी

पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में आय और संपत्ति की विषमताओं का मूल कारण निजी संपत्ति और उत्तराधिकार की व्यवस्थाएँ हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं को समाप्त कर एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था आय की विषमताओं को कम करने में समर्थ होती है। यह ध्यान रहे कि किसी भी व्यवस्था में आय और संपत्ति की पूर्ण समानता को न तो वांछनीय माना जाता है और न ही यह व्यवहारिक है।



### (v) वर्ग संघर्ष की समाप्ति

पूँजी अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों और प्रबंधकों के हित भिन्न होते हैं। ये दोनों वर्ग ही अपनी आय और लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। इसी से पूँजीवाद में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। समाजवाद में वर्गों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। सभी व्यक्ति श्रमिक होते हैं इसलिये कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता। सभी सह-कर्मी होते हैं।

### आज के विश्व में समाजवाद

रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के अनेक देशों को समाजवादी देश कहा जाता है। परन्तु अब उनमें परिवर्तन हो रहा है तथा आर्थिक विकास के लिये वे अपने देशों में उदारीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

### (s) मिश्रित अर्थव्यवस्था

मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूँजीवाद की सबसे अच्छी विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः इनमें पूँजीवादी स्वतंत्र उद्यम और समाजवादी सरकारी नियंत्रणों के कुछ तत्व मिले रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों का सह-अस्तित्व रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

#### (i) निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रकों का सह-अस्तित्व

निजी क्षेत्रक में वे उत्पादन इकाइयां आती हैं जो निजी स्वामित्व में होती हैं तथा लाभ के उद्देश्य के लिये कार्य करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक में वे उत्पादन इकाइयां सम्मिलित की जाती हैं जो सरकार के स्वामित्व में होती हैं तथा सामाजिक कल्याण के लिये कार्य करती हैं। सामान्यतः दोनों क्षेत्रकों के आर्थिक कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन रहता है। सरकार अपनी लाइसेंस, करारोपण, कीमत, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों द्वारा निजी क्षेत्रक के कार्यों पर नियंत्रण और उनका नियमन करती है।

#### (ii) व्यक्तिगत स्वतंत्रता

व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करने के लिये आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। वे अपना व्यवसाय और उपभोग चुनने के लिये स्वतंत्र होते हैं। परन्तु उत्पादकों को श्रमिकों और उपभोक्ताओं का शोषण करने की छूट नहीं दी जाती है। जन-कल्याण की दृष्टि से सरकार उन पर कुछ नियंत्रण लागू करती है। उदाहरणार्थ, सरकार हानिप्रद वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर रोक लगाती है। परन्तु सरकार द्वारा जनहित में बनाये गये कानूनों और प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए निजी क्षेत्र 'पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग' कर सकता है।

#### (iii) आर्थिक नियोजन

सरकार दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण कर अर्थव्यवस्था के विकास में निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों के कार्यक्षेत्रों व दायित्वों का निर्धारण करती है। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है अतः वही उसके उत्पादन लक्ष्यों और योजनाओं का निर्धारण भी करती है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, समर्थन, सहारा तथा आर्थिक सहायताओं आदि के माध्यम से राष्ट्रीय वरीयताओं के अनुसार कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाता है।



टिप्पणी

## (iv) कीमत प्रणाली

कीमतों संसाधनों के आबंटन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ क्षेत्रकों में निर्देशित कीमतों भी अपनाई जाती हैं। सरकार लक्ष्य समूहों के लाभ के लिये कीमतों में आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। सरकार का ध्येय जनसामान्य का हित संवर्धन होता है। जो व्यक्ति बाजार कीमतों पर आवश्यक उपभोग सामग्री खरीदने की स्थिति में नहीं होते, सरकार उन्हें रियायती कीमतों पर (या निःशुल्क भी) वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

अतः एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन सामान्य को तथा समाज के कमजोर वर्गों के हित-संवर्धन में सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहारा, दोनों ही उपलब्ध रहते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था समझी जाती है क्योंकि यहां आर्थिक नियोजन के साथ-साथ निजी व सार्वजनिक क्षेत्रकों के आर्थिक कार्य क्षेत्र स्पष्टतया परिभाषित हैं। यू.एस.ए., यू.के. आदि देश भी जो पूंजीवादी देश कहे जाते थे, आर्थिक विकास में इनकी सरकारों की सक्रिय भूमिका के कारण अब मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं।



## पाठगत प्रश्न 4.1

1. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य/असत्य हैं?
  - (i) संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को अमीर और गरीब वर्गों में बांट सकते हैं।
  - (ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है।
  - (iii) चयन की स्वतंत्रता, लाभ अधिकतम करना और निजी संपत्ति एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं।
  - (iv) एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है।
2. कोष्ठक में दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें।
  - (i) पूंजीवादी/मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली ..... भूमिका निभाती है। (बहुत महत्वपूर्ण/बहुत सीमित)
  - (ii) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चयन की स्वतंत्रता को ..... कहते हैं। (उपभोक्ता का प्रभुत्व/उपभोक्ता का अतिरेक)
  - (iii) समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं ..... अर्थव्यवस्थाएं हैं। (केन्द्रीय नियोजित/विकेन्द्रीकृत)
  - (iv) ..... अर्थव्यवस्था में जनता धन संग्रह कर उसे अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को दे सकती है। (समाजवादी/पूंजीवादी)
  - (v) एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों का ..... होता है। (सह-अस्तित्व/अस्तित्व नहीं होता)



टिप्पणी

3. विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की निम्न विशेषताओं को वर्गीकृत कर उन्हें उपयुक्त खानों में लिखें:

लाभ का ध्येय, केन्द्रीय नियोजन, उपभोक्ता का प्रभुत्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, उत्तराधिकार के कानून, सामाजिक कल्याण, सरकारी नियमन, आर्थिक सहायता, प्रतियोगिता, कीमत प्रणाली, विषमताएं, वर्ग संघर्ष का अभाव, आर्थिक नियोजन, चयन की सीमित स्वतंत्रता

पूंजीवादी  
अर्थव्यवस्था

समाजवादी  
अर्थव्यवस्था

मिश्रित  
अर्थव्यवस्था

#### 4.2.2 विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार

विकास के स्तर के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:

- (i) विकसित अर्थव्यवस्था
- (ii) विकासशील अर्थव्यवस्था

किसी अर्थव्यवस्था को उसके वास्तविक राष्ट्रीय आय, तथा उसकी जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय और जीवन के निर्वाह स्तर के आधार पर उसे विकसित या अमीर और विकासशील अथवा गरीब देश कहा जाता है। विकसित देशों में राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय तथा पूंजी निर्माण अर्थात् बचत और निवेश के स्तर उच्च होते हैं। उनके मानवीय संसाधन अधिक शिक्षित होते हैं। वहां जन सुविधाओं, चिकित्सा-स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रबंध सुविधाएं, बेहतर होती हैं और मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर निम्न होती हैं। साथ ही वहां औद्योगिक और सामाजिक आधारिक संरचना तथा पूंजी और वित्त बाजार भी विकसित होते हैं। संक्षेप में, विकसित देशों में जीवन स्तर उन्नत होता है।

विकासशील देश विकास की सीढ़ी पर काफी नीचे होते हैं। उन्हें कई बार अल्प विकसति, पिछड़े या गरीब देश भी कहा जाता है। परन्तु अर्थशास्त्री उन्हें विकासशील कहना बेहतर मानते हैं क्योंकि इस शब्द से गतिशीलता का भास होता है। इन देशों में राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय निम्न होती हैं। इनके कृषि और उद्योग पिछड़े होते हैं, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। यद्यपि इन देशों में निर्यात से आय होती है पर अधिकांशतः ये प्राथमिक और कृषि उत्पाद ही निर्यात कर पाते हैं। संक्षेप में निम्न जीवन स्तर के इन देशों में उच्च शिशु मृत्यु दर, जन्म एवं मृत्यु दरें और स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंध तथा आधारिक संरचना का स्तर भी निम्न होता है। अतः आर्थिक विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है - इसके कई अलग-अलग अर्थ भी हो सकते हैं। यद्यपि आप पहले ही पढ़ चुके हैं परन्तु अगले कुछ पृष्ठों में आर्थिक विकास और इसके निर्धारकों पर चर्चा करना लाभदायक होगा। साथ ही हम आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि का भेद भी स्पष्ट करेंगे।



टिप्पणी

### 4.3 आर्थिक विकास का अर्थ

आर्थिक संवृद्धि राष्ट्रीय आय में निरन्तररूप से होने वाली वृद्धि है। यह आर्थिक विकास से भिन्न है। जनसंख्या में अन्तरों का ध्यान में रखते हुए यह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में दिखाई पड़ती है (प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय ÷ कुल जनसंख्या)

यद्यपि राष्ट्रीय आय की वृद्धि में प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव अथवा अल्पकालिक परिवर्तन हो सकते हैं, पर राष्ट्रीय आय की दीर्घकालिक वृद्धि ही आर्थिक संवृद्धि कहलाती है।

दूसरी ओर, आर्थिक विकास में आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ देश में जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को सुधारने वाले आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ किसी देश में गरीबी और बेरोजगारी में कमी, आय और संपत्ति की विषमताओं में कमी, साक्षरता दर में सुधार, स्वास्थ्य-जनस्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी पर्यावरणीय मानकों में सुधार जैसे आर्थिक परिवर्तन आते हैं जिनसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो हम इस संवृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। जन-समान्य के जीवन स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले ये आर्थिक परिवर्तन आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं। अन्यथा आर्थिक संवृद्धि के बावजूद भी लोगों का जीवन स्तर सुधर नहीं पायेगा। यदि समाज का अमीर वर्ग ही संवृद्धि के सभी लाभों को हस्तगत कर ले तो अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब पहले से अधिक गरीब हो जायेंगे। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक संवृद्धि की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत है। इसमें केवल आर्थिक संवृद्धि ही नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य अनेक आर्थिक परिवर्तन भी समाहित रहते हैं।

### 4.4 आर्थिक विकास के निर्धारक

आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर अनेक आर्थिक और गैर-आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है।

कुछ प्रमुख आर्थिक कारक इस प्रकार हैं :

- (i) **प्राकृतिक संसाधन:** प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक संवृद्धि और विकास को सुगम बनाती है और इनकी गति में वृद्धि करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन साधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता संवृद्धि दर को प्रभावित करती है।
- (ii) **मानवीय संसाधन:** समाज के मानवीय संसाधनों अथवा जनसंख्या की मात्रा और गुणवत्ता भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अन्य बाते समान रहने पर शिक्षित और तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उच्च संवृद्धि दर की प्राप्ति में सहायक रहती है। दूसरी ओर, निरक्षर एवं अकुशल जनसंख्या के कारण आर्थिक संवृद्धि मन्द हो जाती है।
- (iii) **पूँजी निर्माण:** पूँजीगत पदार्थों के भण्डार का तीव्र आर्थिक संवृद्धि पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। इस भण्डार को बढ़ाने के लिये उच्च दर से बचत आवश्यक है। इन बचतों का निवेश भी होना चाहिये। बचत और निवेश दरों के साथ-साथ संवृद्धि दर पूँजी उत्पाद अनुपात



पर भी निर्भर करेगी। यदि किसी विकासशील देश में आंतरिक बचत की दर पर्याप्त नहीं हो तो सरकार पूँजी निर्माण तथा संवृद्धि दर में वृद्धि के लिये विदेशी सहायता भी ले सकती है।

#### (iv) प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी का आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रौद्योगिकी प्रगति निरंतर शोध और विकास पर निर्भर करती हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति के सहारे कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की कमी और निम्न उत्पादकता की बाधाओं को पार कर सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने मानव संसाधनों में निवेश करती हैं।

इन आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अनेक गैर-आर्थिक कारक भी हैं: (i) जाति प्रथा, (ii) परिवार का प्रकार, (iii) वंशानुगत कारक और (iv) सरकारी नीतियां। इन सबका भी आर्थिक संवृद्धि और विकास की दर पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास को मापना तथा उसका केवल एक सूचक बनाना बहुत कठिन कार्य है। आर्थिक विकास के सर्वाधिक प्रचलित सूचक प्रति व्यक्ति आय में अनेक गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। इस सूचक में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण के पतन के समायोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे उद्योगों के धुए, उनके जल-प्रदूषक प्रवाहों तथा अन्य जल और वायु को हानि पहुंचाने वाले सह-उत्पाद वनों को काटना तथा इमारती लकड़ी के विक्रय से प्राप्त आय को एक आर्थिक गतिविधि मान लिया जाएगा तथा आय को राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में जोड़ दिया जाएगा परन्तु इस गतिविधि से बन सम्पदा को हुई हानि की कोई क्रृणात्मक प्रवष्टि राष्ट्रीय लेखे के आंकड़ों में नहीं की जाती। आजकल अनेक अर्थशास्त्री गंभीरतापूर्वक ऐसे नये विकास सूचक की रचना पर कार्य कर रहे हैं जिसमें समाज की पर्यावरण लागतों का लेखा भी संभव हो तथा उसे समाज के कल्याण के सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सके।

### 4.5 आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि में अन्तर

आर्थिक संवृद्धि एक अल्पकालिक माप है तथा इससे अभिप्राय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वार्षिक परिवर्तनों से है। परन्तु आय सूचक राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में कोई जानकारी नहीं देता। एक अन्य बात यह है कि आय विधि में अनुत्पादक और निर्धारक संवृद्धि तथा सामाजिक दृष्टि से उत्पादक एवं सार्थक संवृद्धि में भी कोई भेद नहीं किया जाता। दूसरी ओर, आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक माप है। आर्थिक विकास से अभिप्राय जीवन स्तर में हुए कुल सुधार तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार से है। इसमें आयसूचक के अतिरिक्त कुछ गैर-आर्थिक सूचकों को भी समाहित किया जाता है। ये हैं : जन्म के समय उच्च जीवन प्रत्याशा, निम्न शिशु मृत्यु दर तथा उच्च साक्षरता दर। इन गैर-आर्थिक सूचकों में सुधार सूचित करता है कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं सामाजिक आयोग (UNESCO) तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) जैसी विश्व संस्थाएं अब मूलभूत आवश्यकता आधारित संकल्पनाओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन सुविधाओं,



टिप्पणी



### पाठगत प्रश्न 4.2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

1. विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के दो वर्ग कौन से हैं?
2. आर्थिक विकास का सरल अर्थ लिखिये।
3. आर्थिक विकास के निर्धारकों के आर्थिक कारक दीजिये।
4. विकास को प्रभावित करने वाले गैर-आर्थिक कारक क्या हैं?
5. विकास मापन की आय विधि में सबसे गंभीर त्रुटि क्या है?
6. आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक विकास में भेद कीजिये।
7. आर्थिक संवृद्धि के लिये पूँजी निर्माण किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है?



### आपने क्या सीखा

- इस पाठ में हमने अर्थव्यवस्था का अर्थ जाना है। यह सामाजिक एवं कानूनी रूप से मान्य उन गतिविधियों की पद्धति है जिसके अनुरूप चलकर समाज अपनी आजीविका कमाता है। इसे मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि के लिये बनाई गई सहयोग व्यवस्था भी कहते हैं।
- आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था में, ‘तुम मेरे लिये यह करो’ ‘मैं तुम्हारे लिये वह करूँगा’ का सहयोग पर्याप्त नहीं रहता। अब तो देश की सीमाओं के आर-पार भी सहयोग आवश्यक हो गया है। अतः अर्थव्यवस्था को परस्पर सहयोग और विनिमय की व्यवस्था भी माना जा सकता है।
- उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं :



टिप्पणी

- (i) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
- (ii) समाजवादी अर्थव्यवस्था
- (iii) मिश्रित अर्थव्यवस्था
- विकास के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :
  - (i) विकसित अर्थव्यवस्था
  - (ii) विकासशील अर्थव्यवस्था
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वैयक्तिक स्वतंत्रता और प्रतियोगिता को अधिक महत्व देती है। उपभोक्ता 'राजा' के समान है तथा वह कीमत प्रणाली, लाभ के उद्देश्य और बाजार के माध्यम से संसाधनों के आबंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- समाजवादी अर्थव्यवस्था सामूहिक स्वामित्व, सामाजिक हित और आर्थिक नियोजक पर बल देती है। यहां विषमताएं कम होती हैं तथा वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों प्रणालियों के सदगुणों को महत्व देती है। यहां सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहता है। सार्वजनिक क्षेत्रक समाजवादी अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर कार्य करता है।
- विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय और उनका जीवन स्तर उच्च होता है।
- दूसरी ओर, अल्पविकसित अथवा गरीब देशों में आय, बचत तथा निवेश का स्तर निम्न होता है, इसलिये इनका जीवन स्तर भी निम्न होता है।
- आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अनेक आर्थिक और गैर-आर्थिक निर्धारक होते हैं।
- आर्थिक विकास और संवृद्धि में एक अन्तर है। सामान्यतः आर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय कुछ क्षेत्रों तथा चरों में अल्पकालिक सुधार से होता है। दूसरी ओर, आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाले अनेक कारकों में दीर्घकालिक सुधार की अवधारणा है।



### पाठान्त्र प्रश्न

1. अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइये।
2. 'अर्थव्यवस्था पारस्परिक सहयोग और विनिमय की व्यवस्था है'। विवेचना कीजिये।
3. उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार समझाइये।

4. आर्थिक विकास तथा आर्थिक संवृद्धि में भेद कीजिये।
5. आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक क्या होते हैं?



### पाठगत प्रश्नों के उत्तर



टिप्पणी

#### पाठगत प्रश्न 4.1

1. (i) असत्य      (ii) सत्य      (iii) असत्य      (iv) सत्य
2. (i) बहुत महत्वपूर्ण      (ii) उपभोक्ता की सत्ता      (iii) केन्द्रिय रूप से प्रायोजित  
 (iv) पूंजीवादी      (v) सह-अस्तित्व
- 3.

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था	समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित अर्थव्यवस्था
लाभ का ध्येय	केन्द्रीय नियोजन	सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक
उपभोक्ता का प्रभुत्व	सामाजिक हित	सरकारी नियमन
उत्तराधिकार का नियम	वर्ग संघर्ष का अभाव	आर्थिक आयोजन
प्रतियोगिता		आर्थिक सहायता
कीमत प्रणाली		चयन की सीमित स्वतंत्रता
विषमताएं		

#### पाठगत प्रश्न 4.2

1. विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकासशील अर्थव्यवस्था।
2. आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है।
3. प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी।
4. जाति प्रथा, परिवार का प्रकार, वंशानुगत।
5. इसमें पर्यावरणीय लागतों तथा संसाधनों के क्षय को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
6. आर्थिक संवृद्धि वास्तविक आय में अल्पकालिक सुधार है जबकि आर्थिक विकास में दीर्घकालिक आय में वृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर और गुणवत्ता में भी सुधार होते हैं।
7. पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहने पर पूंजी निर्माण संवृद्धि दर को निर्धारित करता है।